IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 13, 2022

ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ और रणनीतियाँ

विक्रम जीत मेहरा
शोधार्थी, (भूगोल विभाग)
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

डॉ. सुनील कुमार
सह–आचार्य, (भूगोल विभाग)
टांटिया विश्वविद्यालय,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सारांश :

गाँवों में बसने वाले भारत के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना तब तक साकार नहीं हो सकती, जब तक कि गाँव एवं ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं दी जाती। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न केवल राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह समग्र समाज की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने केन्द्र के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि ग्रामीण समाज की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हो सके।

राजस्थान, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में तीव्र गति से विकास कर रहा है, अपने नियोजित विकास के प्रयासों के जरिए अग्रिम पंक्ति के राज्यों में अपना स्थान बनाते हुए विकास की दिशा में कई कदम उठा रहा है। यहाँ की राज्य सरकार ने विकास की गति को और तेज करने के लिए ठोस योजनाएँ बनाई हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

इसके साथ ही, प्राकृतिक विपदाएँ जैसे सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाएँ विकास में बड़ी बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं। राजस्थान की राज्य सरकार इन विपदाओं से निपटने के लिए लगातार सजग और सचेत रही है। इसके लिए वह न केवल तत्काल राहत उपायों की योजना बनाती है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतियाँ भी अपनाती है, ताकि भविष्य में इन विपदाओं का प्रभाव न्यूनतम हो और विकास प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इस प्रकार, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि विकास की गति लगातार बनी रहे और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद गाँवों का सर्वांगीण विकास निरंतर आगे बढ़े।

मूल बिंदु

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास,शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में सुधार, प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए सरकार की तैयारी

परिचय

"विश्व आयोग" के अनुसार विकास वह संकल्पना है, जिसका तात्पर्य वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की क्षमताओं से समझौता नहीं करना है। ग्रामीण विकास का उद्देश्य केवल ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारना नहीं, बल्कि समग्र रूप से ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है। यह एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कृषि, सहायक गतिविधियाँ, कुटीर उद्योग, शिल्पकारी, सामाजिक–आर्थिक अधोसंरचना, सामुदायिक सेवाएं, और मानव संसाधनों का विकास शामिल है। ग्रामीण विकास को विभिन्न भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संस्थागत कारकों के बीच आपसी सम्बन्धों का परिणाम माना जा सकता है।

ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक परिकल्पना को स्पष्ट करते हुए, पाँच प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला बिंदु है शिक्षा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने से समग्र विकास संभव है। दूसरा बिंदु है स्वास्थ्य जागरण केंद्रित कार्यक्रम, जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और जन जागरूकता फैलाने में सहायक होंगे। तीसरा बिंदु कृषि है, जिसमें पारंपरिक खेती को जैविक कृषि की मूल्यवर्धक प्रक्रिया से जोड़ना आवश्यक है। चौथा बिंदु सामाजिक वातावरण निर्माण है, जिसमें महिला मंडलियों का गठन, ग्रामीण संरचनाओं का सशक्तिकरण, वाचनालय, क्रीड़ा मंडली का गठन और ग्रामोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। पाँचवाँ और अंतिम बिंदु स्वावलंबन है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को सशक्त और आधुनिक बनाना आवश्यक है। इन सभी गतिविधियों को संचालित करने वाले गाँवों को प्रभात ग्राम की संज्ञा दी गई है, जो ग्रामीण विकास की संकल्पना को साकार करने वाले होंगे। इसके साथ ही, कुछ गांवों को किरण ग्राम और जो इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए कुछ

शुरुआत करेंगे, उन्हें उदय ग्राम कहा गया है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर, ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास के लक्ष्य और उद्देश्य

1. कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धिः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना।

2. लाभदायक रोजगार की सृजनाः सभी ग्रामीणों के लिए लाभदायक रोजगार पैदा करना।

3. आत्मनिर्भर गाँवों का निर्माणः गाँवों को आत्मनिर्भर एवं आत्मपोषित बनाना।

4. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षणः प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए मानव एवं प्रकृति के मध्य पारिस्थितिक संतुलन का बनाए रखना।

5. आर्थिक विकास में भागीदारीः देश के आर्थिक विकास में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाना।

6. स्वार्थरहित नेतृत्व का प्रोत्साहनः स्वार्थरहित नेतृत्व को प्रोत्साहित करना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण विकास हेतु पंचवर्षीय योजनावार निम्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किये गये–

1. **प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–1956)**
   (अ) सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952
   (ब) नेशनल एक्सटेशन स्कीम, 1953

2. **द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1951–1961)**
   (अ) खादी और ग्रामोद्योग, 1957
   (ब) बहुउद्देशीय आदिवासी विकास खण्ड, 1959

(स) पैकेज प्रोग्राम, 1960

(द) इन्टेसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट प्रोग्राम, 1960

3. तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–1966)

(अ) एप्लाइड न्यूट्रीशियन प्रोग्राम, 1962

(ब) इन्टेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, 1964

(स) हाई यीलिडिंग वैरायटी प्रोग्राम, 1966

(द) फारमर्स ट्रेडिंग एजूकेशन, 1966

(य) कुआ निर्माण योजना, 1966

(र) ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, 1967

(ल) आदिवासी विकास खण्ड, 1968

(व) रूरल मेन पॉवर कार्यक्रम, 1969

4. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–1974)

(अ) सूखा संभाव्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम,

(ब) क्रेश स्कीम फॉर रूरल एम्पलायमेंट, 1971

(स) स्माल फारमर्स डवलपमेंट एजेन्सी, 1971

(द) ट्राईबल एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, 1972

(य) पायलेट प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्रोग्राम, 1972

(र) पायलेट इन्टेंसिव रूरल एम्पलायमेंट प्रोग्राम, 1972

(ल) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 1972

(व) कमाण्ड एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, 1974

5. पंचम पंचवर्षीय योजना (1974–1979)

(अ) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 1975

(ब) स्पेशियल लाईव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, 1975

(स) काम के बदले अनाज योजना, 1977

(द) अन्त्योदय योजना, 1977

6. षष्ठम पंचवर्षीय योजना (1980–1985)

(अ) मरूस्थल विकास योजना, 1980

(ब) समग्र ग्राम विकास योजना

(स) ग्रामीण युवाओं के लिये स्वरोजगार योजना, 1980

(द) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1980

7. सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985–1990)

(अ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम,

(ब) जवाहर रोजगार योजना

(स) सुनिश्चित रोजगार योजना

8. अष्ठम पंचवर्षीय योजना (1992–1997)

(अ) 1 लाख कुओं की योजना,

(ब) इन्दिरा आवास योजना

(स) गंगा कल्याण योजना

9. नवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002)

(अ) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना,

(ब) प्रधानमंत्री रोजगार योजना

(स) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किट की आपूर्ति योजना

(द) स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, 1999

10. दशम पंचवर्षीय योजना (2002–2007)

(अ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,

(ब) राष्ट्रीय गारंटी रोजगार योजना, 2004

11. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012)

(अ) सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करवाना

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान देना

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017)

(अ) समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोड आवागमन की उपलब्धता को बढ़ाना

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था

(स) 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करना

Reference

1. एपथोर्प आर. (1970) – पीपल, प्लानिंग एण्ड डवलपमेन्ट स्टडीज, फेन्क क्रॉस लन्दन

2. अरोड़ा, आर.सी. (1979) – इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेन्ट, एस. चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली

3. अटल योगेश (सम्पादित) 1991 – कल्चर डवलपमेन्ट इन्टरफेस, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली

4. अम्बेडकर, एस.एन. (1994) – इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम : इम्पलीमेन्टेशन प्रोसेस, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर

5. आहूजा कान्ता एण्ड भार्गव प्रदीप (1978) – इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेन्ट प्रोग्राम – ए इवेल्यूशन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, आई.डी.एस., जयपुर

6. बसु, डी.के. एण्ड आर. सिसेन (सम्पादित) (1986) – इकोनॉमिक एण्ड सोशल डवलपमेन्ट इन इण्डिया, नई दिल्ली

7. भादुरी, अमित एण्ड रहमान मो. अन्सार (1982) – स्टडीज इन रूरल पार्टिशिपेशन, ऑक्सफोर्ड एण्ड आई.वी.एच. पब्लिकेशन कम्पनी, नई दिल्ली

8. भटनागर, पी.ए. (1982) – कम्यूनिटी डवलपमेन्ट प्रोग्राम – ए साइको सोशल स्टडी, प्रकाश प्रिंटिग प्रेस, नागपुर

9. चेम्बर्स रोबर्ट (1974) – मैनेजिंग रूरल डवलपमेन्ट आइडियाज एण्ड एक्सपीरियंस फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका – स्केन्डेवियन इंस्टीट्यूट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज, उपासला

10. चेम्बर्स रोबर्ट (1983) – रूरल डवलपमेन्ट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट, लोंगमेन साइंटिफिक एण्ड टेक्नीकल, इंग्लैण्ड

11. चार्ल्स, के.जे. (1983) – टोटल डवलपमेन्ट, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा. लि., नई दिल्ली

12. चटर्जी, विश्वबन्धु (1969) – माइक्रो स्टडीज इन कम्यूनिटी डवलपमेन्ट, एटलिंग पब्लिकेशन्स (प्रा.) लि., नई दिल्ली

13. दान्तेवाला, एम.एल. गुप्ता, आर., डिसूजा, के. (स.) 1986 – 'एशियन सेमीनार ऑन रूरल डवलपमेन्ट' – द इंडियन एक्सपीरियन्स, ऑक्सफोर्ड एण्ड आर.बी.एच. पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

14. देसाई, ए.आर. (1984) – इण्डियाज पाथ ऑफ डवलपमेन्ट, पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई

15. दान्तेवाला, एम.एल. गुप्ता, आर., डिसूजा, के. (स.) 1986 – 'एशियन सेमीनार ऑन रूरल डवलपमेन्ट' – द इंडियन एक्सपीरियन्स, ऑक्सफोर्ड, एण्ड आर.बी.एच. पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली

16. देसाई, ए.आर. (1984) – इण्डियाज पाथ ऑफ डवलपमेन्ट, पॉपुलर प्रकाशन, बम्बई

ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 13, 2022

17. मिश्रा आर. पी. एण्ड सुन्दरम (1979)– रूरल एशिया डवलपमेन्ट पर्सपेक्टिव एण्ड एप्रोचस, न्यू दिल्ली, स्टार्टिंग पब्लिकेशन पी. 428